

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 55]

नवा रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 17 जनवरी 2025 — पौष 27, शक 1946

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 17 जनवरी 2025

क्रमांक 620/डी. 05/21-अ/प्रारू./छ. ग./25. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक 16-1-2025 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल सिन्हा, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 3 सन् 2025)

छत्तीसगढ़ नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2024

छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) के अग्रतर संशोधन हेतु अधिनियम ।

भारत गणराज्य के पचछतरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

- संक्षिप्त नाम,
विस्तार तथा
प्रारंभ.
1. (1) यह अधिनियम, छत्तीसगढ़ नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2024 कहलायेगा।
(2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा।
(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

धारा 3 में
संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) की धारा 3 के खण्ड (25-क) के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाये, अर्थात् :-

“परन्तु, अन्य पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या से अभिप्रेत है, ऐसी जनसंख्या के आंकड़े, जिसका निर्धारण विहित रीति से किया गया हो।”

धारा 19 का
संशोधन.

3. मूल अधिनियम की धारा 19 में,—
(एक) उप-धारा (1) के खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:-

“(क) नगरपालिक क्षेत्र से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा निर्वाचित अध्यक्ष अर्थात् सभापति;”

(दो) उप-धारा (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-धारा प्रतिस्थापित की जाये, अर्थात्:-

“(4) यदि कोई नगरपालिका क्षेत्र, अध्यक्ष का निर्वाचन करने में असफल रहे या कोई वार्ड पार्षद का निर्वाचन करने में असफल रहे, तो यथास्थिति, ऐसे नगरपालिका क्षेत्र या वार्ड के स्थान को भरने के लिए छः माह के भीतर नई निर्वाचन कार्यवाहियाँ प्रारंभ की जायेंगी और जब तक उस स्थान को भरा नहीं जाता, उसे आकस्मिक रिक्ति समझा जाएगा:

परंतु अधिनियम के अधीन उपाध्यक्ष या किन्हीं समितियों के निर्वाचन की कार्यवाहियाँ, ऐसे स्थान का निर्वाचन लंबित रहते स्थगित नहीं की जायेंगी।”

4. मूल अधिनियम की धारा 20 की उप-धारा (2) के खण्ड (ख) के उप-खण्ड (तीन) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-खण्ड प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:-

धारा 20 का संशोधन.

“(तीन) अध्यक्ष के निर्वाचन की दशा में, नगरपालिका क्षेत्र के किसी मतदाता द्वारा;”

5. मूल अधिनियम की धारा 29-क की उप-धारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-धारा प्रतिस्थापित की जाये, अर्थात्:-

धारा 29-क का संशोधन.

“(2) ऐसी नगरपालिका में जहाँ अनुसूचित जातियों तथा/अथवा अनुसूचित जनजातियों के लिए पचास

प्रतिशत से कम स्थान आरक्षित किये गये हैं, वहां यथासंभव निकटतम रूप से कुल स्थानों की संख्या के पचास प्रतिशत की अधिकतम सीमा के अध्यधीन रहते हुए, शेष स्थान अन्य पिछड़े वर्गों के लिए, उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षित किये जाएंगे और ऐसे स्थान भिन्न-भिन्न वार्डों के लिए चक्रानुक्रम से ऐसी रीति से आवंटित किए जाएंगे जैसा कि विहित किया जाए:

परंतु यह कि, उप-धारा (1) के अधीन अनुसूचित जातियों तथा/अथवा अनुसूचित जनजातियों का कुल आरक्षण पचास प्रतिशत या पचास प्रतिशत से अधिक है, तो अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए स्थान आरक्षित नहीं किया जाएगा:

परन्तु, यह और कि यदि इस प्रकार आरक्षित रखे गए किसी वार्ड से पार्षद के रूप में निर्वाचन के लिए अन्य पिछड़े वर्गों के किसी भी सदस्य द्वारा कोई नामांकन पत्र फाइल नहीं किया जाता है तो, कलेक्टर उस वार्ड को अनारक्षित वार्ड के रूप में घोषित करने के लिए सक्षम होगा।'

धारा 29—ख का
संशोधन.

6. मूल अधिनियम की धारा 29—ख में, —

(एक) उप-धारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-धारा प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

“(2) यथास्थिति, राज्य के नगरपालिका परिषदों और नगर पंचायतों के अध्यक्ष के पदों की कुल संख्या में अनुसूचित जातियों तथा/अथवा अनुसूचित जनजातियों के लिए पचास प्रतिशत से कम स्थान आरक्षित होने पर यथासंभव निकटतम रूप

से कुल स्थानों की संख्या के पचास प्रतिशत की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए शेष स्थान अन्य पिछड़े वर्गों के लिए, उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षित किये जाएंगे:

परन्तु उप-धारा (1) के अधीन अनुसूचित जातियों तथा/अथवा अनुसूचित जनजातियों का कुल आरक्षण पचास प्रतिशत या पचास प्रतिशत से अधिक होने की स्थिति में, अन्य पिछड़े वर्गों के लिए स्थान आरक्षित नहीं किया जाएगा।”

(दो) उप-धारा (4-क) का लोप किया जाये।

7. मूल अधिनियम की धारा 30 में,—

(एक) खंड (ए) का लोप किया जाये।

(दो) खंड (डी) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड जोड़ा जाये,
अर्थात्:—

“(ई) यदि राज्य निर्वाचन आयोग या उसके द्वारा नियुक्त किसी प्राधिकारी का, उसको दिये गये आवेदन पर या स्वप्रेरणा से, ऐसी जांच के पश्चात्, जैसा कि वह ठीक समझे, यह समाधान हो जाता है कि किसी परिषद् के वार्ड से संबंधित विधानसभा की प्रचलित निर्वाचक नामावली में पंजीकृत किसी निर्वाचक का नाम, त्रुटिपूर्ण रूप से शामिल नहीं हुआ है, तो वह परिषद् के संबंधित वार्ड की निर्वाचक नामावली में सम्मिलित करेगा।”

धारा 30 का
संशोधन.

- | | | |
|----------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| धारा 32 का संशोधन. | 8. | मूल अधिनियम की धारा 32 की उप-धारा (1) एवं (2) में, शब्द "पार्षदों" जहाँ कहीं भी आया हो, के पूर्व, शब्द "अध्यक्षों तथा" अन्तःस्थापित किया जाये। |
| धारा 32-क का संशोधन. | 9. | मूल अधिनियम की धारा 32-क की उप-धारा (1) के शीर्षक में, शब्द "पार्षद" के स्थान पर, शब्द "अध्यक्ष" प्रतिस्थापित किया जाये। |
| धारा 32-ख का संशोधन. | 10. | मूल अधिनियम की धारा 32-ख में, शब्द "पार्षद" के स्थान पर, शब्द "अध्यक्ष" प्रतिस्थापित किया जाये। |
| धारा 32-ग का संशोधन. | 11. | मूल अधिनियम की धारा 32-ग के खण्ड (ख) में, शब्द "पार्षद" के पूर्व, शब्द "अध्यक्ष या" अन्तःस्थापित किया जाये। |
| धारा 33 का संशोधन. | 12. | <p>मूल अधिनियम की धारा 33 में,—</p> <p>(एक) शब्द "पार्षदों" के पश्चात्, शब्द "या अध्यक्ष" अन्तःस्थापित किया जाये;</p> <p>(दो) परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:—</p> <p style="padding-left: 40px;">"परन्तु कोई भी व्यक्ति, यथास्थिति पार्षदों के किसी निर्वाचन में या अध्यक्ष के निर्वाचन में एक से अधिक बार मतदान नहीं करेगा।"</p> |
| धारा 34 का संशोधन. | 13. | <p>मूल अधिनियम की धारा 34 में,—</p> <p>(एक) उप-धारा (1) के खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:—</p> <p style="padding-left: 40px;">"(क) यदि वह आयु में 25 वर्ष से कम नहीं है, अध्यक्ष के निर्वाचन हेतु; और"</p> <p>(दो) उप-धारा (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-धारा</p> |

जोड़ी जाये, अर्थात्:-

“(4) यदि कोई व्यक्ति, अध्यक्ष तथा पार्षद दोनों पदों के लिए निर्वाचित हो जाता है, तो उसे निर्वाचित घोषित किए जाने की तारीख से सात दिनों के भीतर किसी एक पद से अपना त्यागपत्र देना होगा।”

14. मूल अधिनियम की धारा 35 में,—

धारा 35 का संशोधन.

(एक) शीर्षक में, शब्द “पार्षद” के पूर्व, शब्द “अध्यक्ष या” अन्तःस्थापित किया जाये।

(दो) खण्ड (घघ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:-

“(घघ) अध्यक्ष की दशा में, आयु पच्चीस वर्ष से कम हो तथा पार्षद की दशा में, आयु इक्कीस वर्ष से कम हो;”।

15. मूल अधिनियम की धारा 36 की उप-धारा (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-धारा जोड़ी जाए, अर्थात् :-

धारा 36 का संशोधन.

“(5) यदि उप-धारा (1) में वर्णित कालावधि के अवसान होने के पूर्व, नगर पालिका/नगर पंचायत पुनर्गठित नहीं की जाती है, तो वह उक्त कालावधि के अवसान हो जाने पर विघटित हो जाएगी और धारा 328 के उपबंध, छः मास से अनधिक कालावधि के लिए लागू होंगे, जिसके भीतर नगरपालिका/नगर पंचायत इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार पुनर्गठित की जाएगी।”

16. मूल अधिनियम की धारा 43 में,—

धारा 43 का संशोधन.

(एक) शीर्षक में, शब्द “उपाध्यक्ष” के पूर्व, शब्द “अध्यक्ष तथा” का लोप किया जाये।

(दो) उप-धारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-धारा प्रतिस्थापित की जाये, अर्थात्:—

“(1) परिषद् के अध्यक्ष तथा निर्वाचित पार्षद, धारा 55 की उप-धारा (1) में यथा निर्दिष्ट अपने प्रथम सम्मेलन में निर्वाचित पार्षदों में से विहित रीति में एक उपाध्यक्ष का निर्वाचन करेंगे।”

(तीन) उप-धारा (3) में, शब्द “उपाध्यक्ष” के पूर्व, शब्द “अध्यक्ष तथा” का लोप किया जाये।

धारा 43—क का संशोधन.

17. मूल अधिनियम की धारा 43—क में,—

(एक) शीर्षक में, शब्द “उपाध्यक्ष” के पूर्व, शब्द “अध्यक्ष या” का लोप किया जाये।

(दो) उप-धारा (1) में, शब्द “उपाध्यक्ष” जहाँ कहीं भी आया हो के पूर्व, शब्द “अध्यक्ष या” का लोप किया जाये।

(तीन) उप-धारा (2) के खण्ड (दो) में, शब्द “उपाध्यक्ष” का लोप किया जाये।

धारा 47 का संशोधन.

18. मूल अधिनियम की धारा 47 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाये, अर्थात्:—

“47. अध्यक्ष का वापस बुलाया जाना.— (1) किसी परिषद् के प्रत्येक अध्यक्ष द्वारा अपना पद तत्काल रिक्त कर दिया गया समझा जाएगा, यदि उसे ऐसी प्रक्रिया के अनुसार, जो कि विहित की जाए, नगरपालिका क्षेत्र के मतदाताओं की कुल संख्या के आधे से अधिक मतदाताओं के बहुमत द्वारा गुप्त मतदान से वापस बुलाया जाए:

परंतु यह कि वापस बुलाने की ऐसी कोई प्रक्रिया तब तक आरंभ नहीं की जाएगी, जब तक कि निर्वाचित पार्षदों की कुल संख्या के कम से कम तीन चौथाई पार्षदों द्वारा प्रस्ताव पर हस्ताक्षर न कर दिए जाएं और उसे कलेक्टर को प्रस्तुत न कर दिया जाए:

परंतु यह और कि ऐसी कोई प्रक्रिया,—

- (एक) उस तारीख से, जिसको कि ऐसा अध्यक्ष निर्वाचित होता है और अपना पद धारण करता है, दो वर्ष की कालावधि के भीतर आरंभ नहीं की जाएगी;
- (दो) यदि उपचुनाव में निर्वाचित अध्यक्ष की आधी कालावधि का अवसान न हो गया हो, आरंभ नहीं की जाएगी:

परंतु यह और भी कि अध्यक्ष को वापस बुलाए जाने की प्रक्रिया, उसकी संपूर्ण अवधि में एक बार ही आरंभ की जाएगी।

- (2) कलेक्टर, अपना समाधान कर लेने और यह सत्यापन कर लेने के पश्चात् कि उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट तीन चौथाई पार्षदों ने वापस बुलाए जाने के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजेगा और राज्य सरकार उसे राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देशित करेगी।
- (3) राज्य निर्वाचन आयोग निर्देश की प्राप्ति पर, वापस बुलाए जाने के प्रस्ताव पर, ऐसी रीति में, जैसा कि विहित की जाए, मतदान करवाने की व्यवस्था करेगा।”

धारा 55 का
संशोधन.

19. मूल अधिनियम की धारा 55 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाये, अर्थात्:-

“55. साधारण निर्वाचन के पश्चात् प्रथम सम्मिलन— (1) मुख्य नगरपालिका अधिकारी, विहित प्राधिकारी के अनुमोदन से, प्रत्येक साधारण निर्वाचन के आगामी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एक मास के भीतर, एक उपाध्यक्ष का निर्वाचन करने के प्रयोजनार्थ निर्वाचित पार्षदों का सम्मिलन बुलाएगा।

(2) उप-धारा (1) के अधीन बुलाए गए परिषद् के प्रथम सम्मिलन की अध्यक्षता, कलेक्टर द्वारा नियुक्त किए गए ऐसे अधिकारी द्वारा, जो नगरपालिका परिषद् के मामले में डिप्टी कलेक्टर के पद श्रेणी से निम्न श्रेणी का न हो तथा नगर पंचायत के मामले में तहसीलदार के पद श्रेणी से निम्न श्रेणी का न हो, की जाएगी और इस अध्याय में अंतर्विष्ट वे समस्त उपबंध, जो परिषद् के सम्मिलनों के संबंध में हैं, यथासंभव ऐसे सम्मिलन के संबंध में लागू होंगे:

परंतु यह कि अध्यक्षता करने वाले अधिकारी को ऐसे सम्मिलन में मत देने का अधिकार नहीं होगा और मतों के बराबर होने की दशा में, परिणाम का विनिश्चय लॉट द्वारा किया जाएगा।”

धारा 56 का
संशोधन.

20. मूल अधिनियम की धारा 56 की उप-धारा (2) में, अंक तथा शब्द “43-क” के पश्चात्, अंक “47” अन्तःस्थापित किया जाये।

धारा 62 का

21. मूल अधिनियम की धारा 62 की उप-धारा (3) के खण्ड

- (तीन) के परंतुक में, अंक तथा शब्द "43—क" के संशोधन.
पश्चात्, शब्द तथा अंक "या 47" अन्तःस्थापित किया जाये।
22. मूल अधिनियम की धारा 63 के परंतुक में, शब्द "किसी समिति" के पूर्व, शब्द "उपाध्यक्ष या" अन्तःस्थापित किया जाये। धारा 63 का संशोधन.
23. मूल अधिनियम की धारा 328 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) में, शब्द "उपाध्यक्ष" जहाँ कहीं भी आये हों, के पूर्व, शब्द "अध्यक्ष तथा" का लोप किया जाये। धारा 328 का संशोधन.
24. छत्तीसगढ़ नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2024 (क्र. 1 सन् 2024) तथा छत्तीसगढ़ नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2024 (क्र. 4 सन् 2024) एतद्द्वारा, निरसन
- निरसित किया जाता है।

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 17 जनवरी 2025

क्रमांक 620/डी. 05/21-अ/प्रारू./छ. ग./25. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2024 (क्रमांक 3 सन् 2025) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल सिन्हा, उप-सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 3 of 2025)

THE CHHATTISGARH MUNICIPALITIES (AMENDMENT)
ACT, 2024.

An Act further to amend the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventy-fifth Year of the Republic of India.

**Short title, extent
and
commencement.**

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Municipalities (Amendment) Act, 2024.
- (2) It shall extend to the whole State of Chhattisgarh.
- (3) It shall come into force with effect from the date of its publication in the Official Gazette.

**Amendment of
Section 3.**

2. After clause (25-a) of Section 3 of the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) (hereinafter referred to as the Principal Act), the following proviso shall be added, namely:-

“Provided that, population of Other Backward Class means, such figures of population, which have been determined in the prescribed manner.”

3. In Section 19 of the Principal Act,–

**Amendment of
Section 19.**

(i) for clause (a) of sub-section (1), the following clause shall be substituted, namely:–

"(a) a President, that is Chairperson, elected by the direct election from the Municipal area;"

(ii) for sub-section (4), the following sub-section shall be substituted, namely:–

"(4) If any municipal area fails to elect a President or any ward fails to elect a councilor, fresh election proceedings shall be commenced for such municipal area or ward, as the case may be, within six months to fill the seat and until the seat is filled, it shall be treated as casual vacancy:

Provided that proceedings of election of Vice-President or any of the Committees under the Act shall

not be stayed,
pending the election
to such seat.”

**Amendment of
Section 20.**

- 4.** For sub-clause (iii) of clause (b) of sub-section (2) of Section 20 of the Principal Act, the following sub-clause shall be substituted, namely:-

“(iii) in the case of election of President by any Voter of the Municipal area;”

**Amendment
of Section 29-A.**

- 5.** For sub-section (2) of Section 29-A of the Principal Act, the following sub-section shall be substituted, namely:-

“(2) In such municipalities where less than fifty percent seats are reserved for Scheduled Castes and/or Scheduled Tribes then as nearly as possible remained seats shall be reserved for Other Backward Classes proportionate to their population but subject to the maximum limit of fifty percent of total seats and such seats shall be allotted by rotation to different wards in such manner as may be prescribed:

Provided that under sub-section (1), if the total

reservation for Scheduled Castes and/or Scheduled Tribes is fifty percent or more than fifty percent, then no seat shall be reserved for Other Backward Classes (OBCs):

Provided further that if no nomination paper is filed for election, as a Councilor from any ward so reserved, by any member of the Other Backward Classes then the Collector shall be competent to declare it, as unreserved."

6. In 29-B of the Principal Act,-

(i) for sub-section (2), the following sub-section shall be substituted, namely:-

"(2) In case, less than fifty percent of the total number of office of Presidents of Municipalities and Nagar Panchayats of the State are reserved for Scheduled Castes and/or Scheduled Tribes, then as nearly as possible remained seats shall be reserved for Other Backward Classes, proportionate to their population but subject to the maximum limit of fifty

**Amendment of
Section 29-B.**

percent of the total seats:

Provided that if the total reservation for Scheduled Castes and/or Scheduled Tribes under sub-section (1) is fifty percent or more than fifty percent, then no seat shall be reserved for Other Backward Classes (OBCs)."

- (ii) sub-section (4-A) shall be omitted.

**Amendment of
Section 30.**

7.

In Section 30 of the Principal Act,-

- (i) clause (a) shall be omitted.
- (ii) after clause (d), the following clause shall be added, namely:-

"(e) If the State Election Commission or an authority appointed by it, on an application or on its own motion, is satisfied after such inquiry as it thinks fit that any voter whose name is registered in the current assembly electoral roll relatable to the ward of the Council, has been erroneously

not included, shall be incorporated in the electoral roll of concerned ward of Council."

- | | | |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 8. | In sub-section (1) and (2) of Section 32 of the Principal Act, before the word "Councilors" wherever they occur, the words "Presidents and" shall be inserted. | Amendment of Section 32. |
| 9. | In heading of sub-section (1) of Section 32-A of the Principal Act, for the word "Councilor", the word "President" shall be substituted. | Amendment of Section 32-A. |
| 10. | In Section 32-B of the Principal Act, for the word "Councilor", the word "President" shall be substituted. | Amendment of Section 32-B. |
| 11. | In clause (b) of Section 32-C of the Principal Act, before the word "Councilor", the words "President or" shall be inserted. | Amendment of Section 32-C. |
| 12. | <p>In Section 33 of the Principal Act, —</p> <p>(i) after the word "Councilors", the words "or President" shall be inserted;</p> <p>(ii) for proviso, the following proviso shall be substituted, namely:-</p> <p style="padding-left: 40px;">"Provided that no person shall vote more than once in any election of the Councilor or an election of</p> | Amendment of Section 33. |

- the President, as the case may be.”
- Amendment of Section 34.** **13.** In Section 34 of the Principal Act, -
- (i) for clause (a) of sub-section (1), the following clause shall be substituted, namely:-
“(a) for the election of President, if he is not less than 25 years of age, and”
 - (ii) after sub-section (3), the following sub-section shall be added, namely:-
“(4) If a person is elected for the office of President and Councilor both, he shall have to resign from one of the offices within seven days from the date on which he is declared to be elected.”
- Amendment of Section 35.** **14.** In Section 35 of the Principal Act, -
- (i) before the word “Councilor”, the words “President or” shall be inserted in the heading.
 - (ii) for clause (dd), the following clause shall be substituted, namely:-
“(dd) is less than twenty-

five years of age, in case of President and is less than twenty-one year of age in case of Councilor;" ...

- 15.** After sub-section (4) of Section 36 of the Principal Act, the following sub-section shall be added, namely :-

**Amendment of
Section 36.**

"(5) If before the expiry of the period mentioned in sub section (1), the municipality/nagar panchayat is not reconstituted, it shall stand dissolved on the expiry of the said period and the provisions of Section 328 shall apply thereto for a period not exceeding six months within which the municipality/ nagar panchayat shall be reconstituted in accordance with the provisions of this Act."

- 16.** In Section 43 of the Principal Act,—

**Amendment of
Section 43.**

- (i) in the heading, before the word "Vice-President", the words "the President and" shall be omitted.

- (ii) for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely:-
 "(1)The President and the elected Councilor of the Council shall, at its first meeting as referred to in sub-section (1) of Section 55, elect a Vice-President from amongst the elected Councilors in the prescribed manner."
- (iii) In sub-section (3), before the word "Vice-President", the words "the President and" shall be omitted.
- Amendment of Section 43-A.** **17.** In Section 43-A of the Principal Act,—
- (i) in the heading, before the word "Vice-President", the words "the President and" shall be omitted.
- (ii) in sub-section (1), before the word "Vice-President", wherever they occur, the words "the President and" shall be omitted.
- (iii) in clause (ii) of sub-section (2), the word "Vice-President" shall be omitted.
- Amendment of Section 47.** **18.** For Section 47 of the Principal Act, the following Section shall be substituted, namely:-

“47. Recalling of President.”-(1)

Every President of a Council shall forthwith be deemed to have vacated his office if he is recalled through a secret ballot by a majority of more than half of the total number of voters of the municipal area casting the vote in accordance with the procedure as may be prescribed:

Provided that no such process of recall shall be initiated unless a proposal is signed by not less than three-fourth of the total number of the elected Councilors and presented to the Collector:

Provided further that no such process shall be initiated,-

- (i) within a period of two years from the date on which such President is elected and enters his office;
- (ii) if half of the period of tenure of the President elected in a by-election has not expired:

Provided also that process for recall of the

President shall be initiated once in his whole term.

(2) The Collector, after satisfying himself and verifying that the three-fourth of the Councilors specified in sub-section (1) have signed the proposal of recall, shall send the proposal to the State Government and the State Government shall make a reference to the State Election Commission.

(3) On receipt of the reference, the State Election Commission shall arrange for voting on the proposal of recall in such manner as may be prescribed."

Amendment of Section 55. **19.**

For Section 55 of the Principal Act, the following Section shall be substituted, namely:-

"55.First Meeting after General Election.— (1) The Chief Municipal Officer shall, with the approval of prescribed authority, within one month from the date of the further publication of the notification of every general election, call a meeting of the elected

Councilors for the purpose of electing a Vice-President.

- (2) The first meeting of the council called under sub-section (1) shall be presided over by such officer not below the rank of Deputy Collector in the case of Municipal Council and not below the rank of Tahsildar in the case of Nagar Panchayat, appointed by the Collector and all provisions contained in this Chapter regarding meetings of the Council shall, as far as may be, apply in respect of such meeting:

Provided that the presiding officer shall not have the right to vote at such meeting and in case of equality of votes, the result shall be decided by lot."

- 20.** In sub-section (2) of Section 56 of the Principal Act, after the figure and word "43-A", the figure "47" shall be inserted.

**Amendment of
Section 56.**

- 21.** In proviso of clause (iii) of sub-section (3) of Section 62 of the Principal Act, after the figure and word "43-A", the word and figure "or 47" shall be inserted.

**Amendment of
Section 62.**

- 22.** In the proviso of Section 63 of the Principal Act, before the word "Chairman", the words

**Amendment of
Section 63.**

		<p>“Vice-President, or the” shall be inserted.</p>
Amendment of Section 328.	23.	<p>In clause (b) of sub-section (1) of Section 328 of the Principal Act, before the word “Vice-President”, wherever they occur, the words “President and” shall be omitted.</p>
Repeal.	24.	<p>The Chhattisgarh Municipalities (Amendment) Ordinance, 2024 (No. 1 of 2024) and the Chhattisgarh Municipalities (Amendment) Ordinance, 2024 (No. 4 of 2024) is hereby, repealed.</p>